यू.पी. राज्य

बनाम

वीर सिंह और अन्य

अप्रैल 28,2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धाराएँ 302/149, 307/149 - दो परिवारों के सदस्यों की हत्या का अभियुक्त - जीवित पीड़ित का साक्ष्य – उसके बयान मृत्यु कालिक घोषणा के रूप में दर्ज किये गए – विचारण न्यायालय ने उसके साक्ष्य पर भरोसा करते हुए 5 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 3 को दोषमुक्त किया - उच्च न्यायालय ने उक्त पाँच अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए यह भी माना कि मृत्यु कालिक घोषणा में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था – अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय का निर्णय अक्षम्य क्योंकि उसने रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्यों पर विचार नहीं किया - मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

धाराएँ 32, 155 और 157 - मृत्यु कालिक घोषणा के रूप में दर्ज बयान - बयान देने वाला जीवित रहता है - बयान की प्रकृति और साक्ष्य मूल्य – अभिनिर्धारित, यह अधिनियम की धारा 32 के तहत दर्ज एक कथन नहीं है, बल्कि धरा 164 दं. प्र.प्र.सं. के

संदर्भ में एक बयान है - इसका उपयोग अधिनियम की धारा 157 के तहत पुष्टि के उद्देश्यों के लिए और धारा 155 के तहत विरोधाभास के लिए किया जा सकता है – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 164।

पीडब्लू 4 द्वारा दी गई जानकारी पर कि उसके परिवार के सभी सदस्यों और एक अन्य परिवार को आरोपी व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया था, शिकायतकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 4 के साक्ष्य और उसके बयान, जिसे म्रत्यु पूर्व दिया गायन बयान कहा जाता है, पर भरोसा करते हुए तीन को बरी कर दिया और पांच अभियुक्तों को धरा 302/149 और 307/149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। दोषी अभियुक्तों, अर्थात् प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि हालांकि प्राथमिकी में उनके नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन मृत्यु कालिक घोषणा में उनका नाम नहीं था। इससे व्यथित होकर, राज्य ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. जब कथित मृत्यु कालिक घोषणा करने वाला जीवित रहता है, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धरा 32 के अंतर्गत कथन नहीं है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के संदर्भ में एक बयान है। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत पुष्टि के उद्देश्य से और धरा 155 के तहत विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है। [794-ए-बी]

रामप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1999] 5 एससीसी 30; सुनील कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जेटी (1997) 2 एससी 1 और जेंटेला विजयवर्धन राव बनाम ए.पी.राज्य, (1996) 6 सुप्रीम 356, संदर्भित।

2. पीडब्लू-4 के बयान को पढ़ने से पता चलता है कि यह पूरी घटना से संबंधित नहीं है। केवल एक सवाल पूछा गया था कि उसे किसने चोट पहुंचाई थी। उच्च न्यायालय के लिए यह निर्धारित करने का कोई अवसर नहीं था कि तथाकथित मृत्यु कालिक घोषणा में प्रतिवादियों का नाम नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ आरोप स्थापित नहीं किया गया है। पीडब्लू-4 ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने सीमित उत्तर क्यों दिया था। उच्च न्यायालय ने इसके प्रभाव पर भी विचार नहीं किया है। अभिलेख पर साक्ष्य का कोई उचित विश्लेषण नहीं था और साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने पर निर्णय दिया गया था। मामला कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। [794-सी-ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 727-729/1998

अपराधिक अपील सं. 749 और 751/1996 और सरकारी अपील सं. 1341/1996 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.12.97 से।

कमलेंद्र मिश्रा के लिए एन.एस.गहलोत, अपीलार्थी की और से।

एम.के. गर्ग के लिए लोकेश कुमार, प्रतिवादी की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति

उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता पर सवाल उठाए हैं जिसमे प्रतिवादियों (इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया था। छोटे बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए 13 लोगों को जिम्मेदार बताया गया। इनमें से एक महेंद्र की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। प्रतिबद्धता के बाद, उन्हें मुजफ्फरनगर के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण का सामना करना पड़ा। जब मुकदमा चल रहा था, उनमें से 4 फरार हो गए हैं और 8 व्यक्तियों पर विचारण चलाया गया। उनमें से तीन, हरदीप, सिंदर सिंह और निशान सिंह को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया, जबकि बाकी पांच जो यहाँ प्रतिवादी हैं, उन्हें अपराधों भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 से संबंधित अपराध के लिए उन्हें पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और धारा 452 से संबंधित अपराध के लिए उन्हें चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। प्रतिवादी वीर सिंह, ताहल सिंह और बलकार सिंह को भी आईपीसी की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि कमरे सिंह और अमरीक सिंह को आईपीसी की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए गए अभियुक्त व्यक्तियों की अपील में, दोषसिद्धि को विवादित फैसले द्वारा अपास्त कर दिया गया है।

अभियोजन संस्करण आवश्यक रूप से इस प्रकार हैः

सरदार गुरदीप सिंह ने मुजफ्फरनगर जिले के पुलिस थाना छिन्झावा में सुबह 14.7.1984 को सुबह लगभग 4 बजे सूचना दी कि उन्होंने गाँव बरनन के पास डोमपुरा गाँव में सरदार और मोहन सिंह के डेरों से गोलियां चलने और चीखने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक ले ली और जस्सा सिंह पुत्र हरबंस सिंह और हुजुर सिंह (पीडब्ल्यू-5) के साथ गुप्त रूप से गोपा सिंह के डेरे की और आया। उसने चांदनी और टोर्च की रोशनी में देखा कि करतार सिंह अपनी छत पर खड़े होकर जोर जोर से अपने बेटे सिंदर सिंह, गिंदर सिंह, महेंद्र और लक्का को पुकार रहा था और उनसे पूरे परिवार और मोहर सिंह को ख़तम करने के लिए कह रहा था, उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है, और यह भी कह रहा था कि उस दिन हिसाब चुकता करना है। जब शिकायतकर्ता और उसके साथी ने उन्हें चुनौती दी, तो उन पर तुरंत कई गोलियां चलाई गईं। शिकायतकर्ता डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय शीशा सिंह की पत्नी हरभजन कौर (पीडब्लू-4) उनके पास आई और उन्हें बताया कि कर्तार सिंह और उनके चार बेटे और उनके साथ 10-12 और लोग, जिनमें अमरीक सिंह, ताहल सिंह, कामिर सिंह, वीर सिंह, संपूर्ण सिंह के बेटे शामिल हैं, उसारपुर हद के सम्पुमा सिंह, बलकार सिंह ने उसके परिवार के सभी सदस्यों और महार सिंह के परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह हरभजन कौर को छिपाने के बाद पुलिस स्टेशन को यह जानकारी देने आया था, और पुलिस से उसकी मदद करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर जाने का अनुरोध किया क्योंकि जब वह घटनास्थल से निकला तो गोलियां चलाई जा रही थीं। उनका उपरोक्त बयान दर्ज किया गया था और चिक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए रिपोर्ट पर

हस्ताक्षर किए थे कि यह उन्हें पढ़कर सुनाई गई थी और उनके निर्देशानुसार सही तरीके से लिखी गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मोह. अख्तर, जो रिपोर्ट लिखे जाने के समय पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, ने मामला उठाया और शिकायतकर्ता के साथ तुरंत घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, उन्होंने घायल हरबंस कौर और उनके बच्चे बच्चू को एक कांस्टेबल के साथ जीप में चिकित्सीय परिक्षण के लिए भेजा। इसके बाद अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण शुरू किया। अन्वेषण पूरा होने पर आरोप पत्र लगाया गया। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-4 के साक्ष्य और कथित रूप से मृत्यु कालिक घोषणा वाले बयान पर भरोसा किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने कुछ को दोषमुक्त कर दिया और वर्तमान प्रतिवादियों को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय का विचार था कि यद्यपि एफआईआर में वर्तमान प्रतिवादियों के नाम दर्शाए गए थे, मृत्यु कालिक घोषणा में उनका नाम नहीं लिया गया था और इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाना था। इस तरह दोषमुक्त होने का वर्तमान निर्णय दर्ज किया जाता है।

अपीलार्थी-राज्य की और से उपस्थित श्री एन.एस. गहलोत, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। तथाकथित मृत्यु कालिक घोषणा जो इस विश्वास के साथ दर्ज की गई थी कि पीडब्लू-4 के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, संक्षेप में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 164 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया एक बयान है, क्योंकि हरभजन कौर जीवित रही थी। जहाँ तक उस पर हमला करने वालों का संबंध है, यह घटना के एक हिस्से से संबंधित है और किसी भी तरह से बाकी घटना से संबंधित नहीं

है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को दोषमुक्त करने का निर्देश देना उचित नहीं था।

प्रतिवादी-अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्तियों के चार समूह हैं। पहले समूह में, आरोपी करतार और उसके चार बेटे शामिल हैं जो विचारण के दौरान फरार हो गए थे। दूसरे में वर्तमान प्रतिवादी शामिल हैं, तीसरा मनदीप और सिंडर का और अंतिम निशान और बलबीर का। जहाँ तक अभियुक्तों के पहले तीन समूहों का संबंध है, उनके एक-दूसरे के साथ कुछ संबंध हैं, लेकिन एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। लेकिन निशान और बलबीर एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। चूंकि एफ़आईआ. में हरदीप, सिंदर और निशान के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। मृत्यु कालिक घोषणा में भी उनका नाम नहीं लिया गया था जिसे संहिता की धारा 164 के तहत बयान माना गया था। यह आग्रह किया गया कि सूचना देने वाले गुरदीप से विचारण के समय पूछताछ नहीं की गई क्योंकि मुकदमे के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जांच के दौरान दिए गए बयान से अलग रहने वाले पीडब्लू-5 की उपस्थिति में पीडब्लू-4 के बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी तरह, पीडब्लू-7, जिसे अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बताया गया था, ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया। पीडब्लू-4 का प्रमाण भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि बहुत सारे भौतिक सुधर पेश किया गए। जहाँ तक वर्तमान प्रतिवादियों का संबंध है, कथित अपराध के लिए कोई मकसद नहीं बताया गया था। मृत्यु कालिक घोषणा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसमें केवल यह कहा गया था कि जब बयान दर्ज किया गया था तो वह होश में थी। चूँकि उच्च न्यायालय ने

अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री और दृष्टिकोण पर विचार किया और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया एक संभावित दृष्टिकोण है, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर निष्पक्ष रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया है।

यह एक सुस्थापित कानून है कि जब कथित मृत्यु कालिक घोषणा करने वाला जीवित रहता है यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') के तहत बयान नहीं है, बल्कि संहिता की धारा 164 के संदर्भ में बयान है। इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत पुष्टि के उद्देश्य से और धारा 155 के तहत विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस स्थिति पर रामप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1999] 5 एससीसी 30, सुनील कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जेटी (1997) 2 एससी 1 और जेंटेला विजयवर्धन राव बनाम ए.पी. राज्य, (1996) 6 सुप्रीम 356 पर प्रकाश डाला गया था।

पीडब्लू-4 के बयान को पढ़ने से पता चलता है कि इसका पूरी घटना से कोई संबंधित नहीं है। केवल एक सवाल पूछा गया था कि बयां देने वाले यानि पीडब्लू-4 को किसने चोट पहुंचाई। उच्च न्यायालय के पास यह कहने का कोई अवसर नहीं था कि तथाकथित म्रत्यु कालिक घोषणा में प्रत्वादियों का नाम नहीं था,इसलिए उनके खिलाफ आरोप स्थापित नहीं किया गया है। पीडब्लू-4 ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने सीमित उत्तर क्यों दिया था। उच्च न्यायालय ने इसके प्रभाव पर भी विचार नहीं किया है। जहाँ तक वर्तमान प्रतिवादियों का संबंध है, इसने अपीलों का

निस्तारण केवल उस आधार पर किया है, जैसा के ऊपर देखा गया है, यह साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं था और साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने पर प्रस्तुत किया गया था। अतः यह निष्कर्ष अक्षम्य है। चूँकि उच्च न्यायालय ने केवल उपरोक्त त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर अपील का निस्तारण किया है और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई का निर्देश देना उचित समझते हैं। इसलिए हम मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं। हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उस हद तक, जब तक कथित मृत्यु कालिक घोषणा के संबंध में उच्च न्यायालय के गलत निष्कर्ष से संबंधित है, जिसके संहिता की धारा 164 के तहत माना जाना चाहिए, को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

अपीलों को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्वीकार किया जाता है।

आर.पी.

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****